बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 300

मजबूत बॉन्ड बाजार

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019-20 के अंतरिम बजट की सराहना करते हुए इसे किसानों, श्रमिकों और मध्य वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने वादा किया कि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जीत हासिल होती है तो समाज के सभी तबकों को और अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा। अंतरिम बजट में कई ऐसे कदम उठाए गए जो एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना से जुड़े हुए हैं। इन कदमों में दो हेक्टेयर रकबे वाले किसानों के लिए आय समर्थन योजना शामिल है। इस योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मुहैया कराने की बात कही जिसमें सरकार का भी समान योगदान है। इसके अलावा 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को आयकर में छूट प्रदान की गई।

उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार की इस पूरी कवायद के बावजूद राजकोषीय घाटे पर कुछ खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। यहां व्यापक बात यह है कि क्या अत्यंत सीमित वित्तीय संसाधनों वाला देश ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चला सकता है? इसके लिए अकेले सरकार को दोष देना अनुचित होगा। सच तो यह है कि मोदी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने कृषि ऋण माफी जैसी कहीं अधिक नुकसानदायक योजनाओं की राह नहीं चुनी। ऐसी योजनाएं ऋण के अनुशासन को भंग करती हैं और इनसे किसानों की स्थिति सुधारने में कुछ खास सहायता नहीं मिलती। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों को विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ऐसी घोषणाएं करने से नहीं रोका। विपक्षी दल भी इसे व्यवहार में अपनाने से पीछे नहीं हटे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह मोदी को तब तक सोने नहीं देंगे जब तक कि देश भर में कृषि ऋण माफी की घोषणा नहीं होती है। उन्होंने यह वादा भी किया है कि अगर आम चुनाव के बाद देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू की जाएगी।

ये तमाम वादे यही जाहिर करते हैं कि देश में ऐसे लोकलुभावनवाद का दौर आ रहा है जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इसके चलते देश में ऐसी राजकोषीय प्रतिबद्धताओं का दौर आ रहा है जिनका स्थायित्व काफी मुश्किल भरा हो सकता है। यकीनी तौर पर विकसित देशों में ऐसी प्रतिबद्धताओं की नाकामी का हश्र हम सब देख ही चुके हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे राजनेता भी उसी दिशा में अग्रसर हैं। ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी बात है जो देश के नीति निर्माताओं को ये वादे करने से रोके। एक तरह से देखा जाए तो इन योजनाओं की वास्तविक वित्तीय लागत का प्रश्न भी सामने है। उदाहरण के लिए एक सुविकसित बॉन्ड बाजार के अभाव में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके तहत बाजार उच्च प्रतिफल और ब्याज के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सके। देश में लोगों को बॉन्ड बाजार से जोड़ने के आधे-अधूरे मन से किए गए प्रयासों को बहुत ही सीमित सफलता मिली है। राजकोषीय लोकलुभावनवाद पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक मजबूत बॉन्ड बाजार हमारी संस्थागत आवश्यकता है। इसकी सफलता सस्ते प्रपत्रों के नकदीकरण, समूचे ऋण परिदृश्य को लेकर निवेशकों की चाह, पर्याप्त हेजिंग की व्यवस्था और व्यवहार्य प्रपत्रों की उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर करेगी। चूंकि ऐसा लगता नहीं कि लोक लुभावनवाद की यह चाह निकट भविष्य में कम होगी, इसलिए भारत को बॉन्ड बाजार के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी।

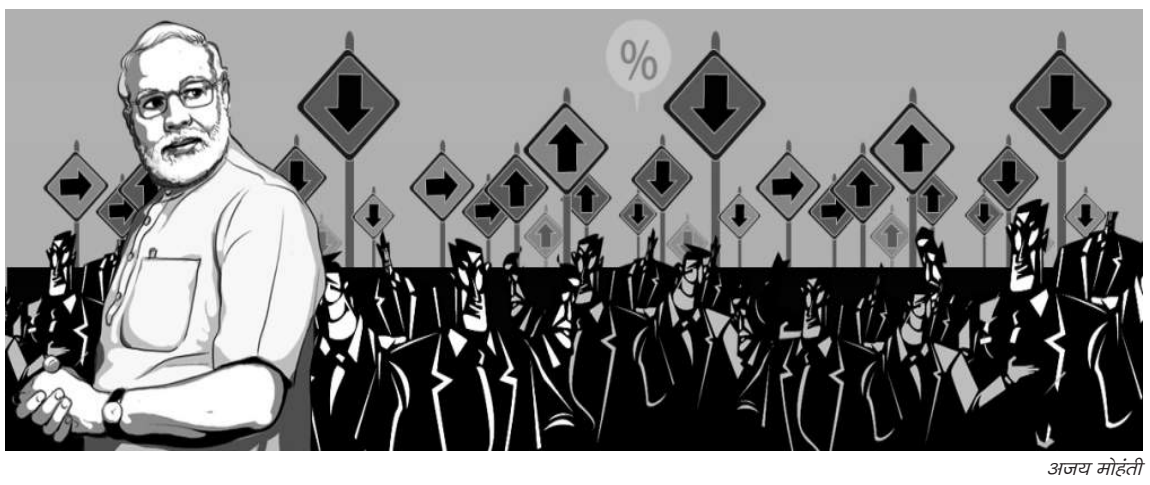

अजय मोहंती

मनमोहन के संप्रग-2 पर भारी मोदी का कार्यकाल

देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी के पांच सटीक कदम यह बताते हैं कि आखिर क्यों यह जरूरी नहीं कि अच्छे आर्थिक कदम, राजनीतिक दृष्टि से बुरे ही हों।

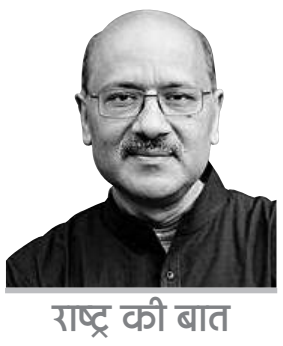

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

बीते पांच वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज को देखें तो आर्थिक मोर्चे पर उसका प्रदर्शन कैसा रहा, इस बारे में दो विपरीत बातें सामने आती हैं और ये पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करती हैं। एक समूह कहेगा कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन शानदार रहा तो दूसरा समूह यह कह सकता है कि सरकार बुरी तरह विफल रही। सरकार के प्रशंसक आंकड़ों की दलील देंगे, आलोचक इसका विरोध करेंगे। परंतु सवाल यह है कि अगर आंकड़ों से छेड़छाड़ की गई हो तो आकलन कैसे होगा? हमें दोनों ध्रुवों के विशेषज्ञों को इस मसले पर लड़ने भिड़ने देना चाहिए और मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में राजनीतिक अर्थव्यवस्था को लेकर व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए।

मोदी सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने को है, ऐसे में नजर डालते हैं पांच ऐसे आर्थिक कदमों पर जिन्हें इस सरकार ने सही ढंग से अंजाम दिया। अपनी बात पर जोर देने के लिए मैं यह दोहराता हूं कि मैं इस तस्वीर को राजनीतिक या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखता हूं, न कि विशुद्ध रूप से आर्थिक। यही वजह है कि मेरी नजर में सबसे बड़ी सकारात्मक घटना है ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी)का सफल क्रियान्वयन।

यह सही है कि अब तक केवल 12 डिफॉल्टरों को इस प्रक्रिया के अधीन किया गया है लेकिन ये 12 सबसे बड़े और ताकतवर लोग हैं। ये उस तरह के लोग हैं जिनके फोन में अधिकांश ताकतवर राजनेताओं और नौकरशाहों के नंबर स्पीड डायल में रहते हैं। जिनकी जेबों में लेनदारी की पर्ची जमा रहती हैं। परंतु तथ्य यही है कोई फोन कॉल उनको बचा नहीं सका। फिर चाहे वह एस्सार के ताकतवर रुइया ही क्यों न हों। यह एक नई तरह की राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

इसे दूसरी तरह से देखते हैं। अगर एक बार आपको पता चल जाए कि एक मित्रवत फोन कॉल आपकी मदद नहीं कर सकता है तब आप यह देश में पूंजीवाद के नए युग के साथ बरताव सीख जाते हैं। यहां अगर आपका कारोबार विफल हुआ तो दिवालिया होना तय है। पूंजीवादी व्यवस्था की मजबूती के लिए समाज को यह कड़वा सबक सीखना होता है कि नाकामी को भी स्वीकार करना होगा। हमारे देश में दिवालियापन को शर्मिंदगी का सबब माना जाता रहा है और छिपाया जाता है।

मुखर रूप से वाम-समाजवादी रुझान वाला लेकिन फोन पर मदद मुहैया कराने वाला राज्य इसमें साझेदार के समान था। मोदी सरकार ने इसका अंत किया। बड़े-बड़े कारोबारी धराशायी हो रहे हैं। यह दौर भारतीय पूंजीवाद के नए स्वरूप के उभार की वजह बन सकता है। मुझे यह राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर अनिवार्य बदलाव नजर आ रहा है।

मोदी सरकार की इस बात के लिए काफी आलोचना हुई है कि कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद उसने पेट्रोलियम पदार्थ के दाम ज्यादा रहने दिए। परंतु इसे लेकर उतनी हायतौबा नहीं मची जैसी संप्रग के दौर में देखने को मिलती थी। यह इसलिए क्योंकि उपभोक्ता महीने के अंत में खरीदारी के समग्र बिल को देखते हैं। मोदी के कार्यकाल में तेल कीमतें अधिक रहीं लेकिन महंगाई, खासतौर पर खाद्य महंगाई में कमी आई। मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है, न ही जीडीपी की तरह उसमें कोई फेरबदल किया गया है। ऐसे में संप्रग के साथ इसकी तुलना करना उचित होगा।

सन 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो संप्रग-2 ने जो अर्थव्यवस्था सौंपी उसमें खुदरा महंगाई 8.33 फीसदी थी। दिसंबर 2018 में यह केवल 2.19 फीसदी है। ध्यान रहे ऐसा तब है जबकि तेल कीमतें ऊंची हैं।

मुद्रास्फीति को कम करना मोदी सरकार के अपेक्षाकृत गैर अकादमिक राजनीतिक अर्थशास्त्र की दूसरी बड़ी सफलता है। अधिकांश भारतीय सरकारें तेल कीमतें कम करने और शहरी बुर्जुआ वर्ग को शांत रखने को तरजीह देतीं।

कीमतों की राजनीति का अपना ही रहस्य है। संप्रग-1 ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार इजाफा किया। इससे किसानों और कृषि श्रमिकों की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई और सरकार को दूसरा कार्यकाल आसानी से मिल गया। दूसरे कार्यकाल में उपभोक्ता खाद्य वस्तुओं की महंगाई आकाश छूने लगी और काफी दबाव उत्पन्न हुआ। नतीजा, सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसमें गिरावट आ रही है। इसके लिए कुछ हद तक एमएसपी न बढ़ाना वजह है। इसके अलावा बाजार की परवाह किए बिना उसने दालों की खेती को खूब बढ़ावा दिया है।

यही कारण है कि किसान गरीब होने लगे और मेहनताना कम होने लगा। महज विगत तीन फसल चक्रों से राजग ने एमएसपी बढ़ाना शुरू किया। परंतु अभी उसके असर का आकलन करना जल्दबाजी होगी। ऐसे में राहुल का यह कहना गलत नहीं कि मोदी के पांच साल के कार्यकाल में किसानों को नुकसान हुआ है।

यह कड़वी राजनीतिक हकीकत है कि जब तक उपभोक्ताओं और किसानों के हित परस्पर विरोधी होंगे, तब तक कीमतें बढ़ने और घटने पर सरकार गिरने का उतना ही जोखिम होगा। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका है और वह है कृषि सुधारों को अंजाम देना। राजग सरकार ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रही है।

सवाल है कि मोदी सरकार ने ईंधन क्षेत्र में जो कर जुटाया, उसका क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर इस बात में निहित है कि उसने राजकोषीय घाटा कम करने में सफलता हासिल की। मतदाताओं को विभिन्न योजनाओं में हजारों करोड़ रुपये की राशि देने के बावजूद सरकार घाटे पर काबू रख सकी क्योंकि उसे तेल से लाभ मिलता रहा।

राजमार्ग निर्माण में भारी निवेश किया गया लेकिन बंदरगाहों, सागरमाला परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र और रेलवे पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि देश का बुनियादी व्यय बीते एक दशक में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में करीब तीन गुना हो गया है। इसमें काफी कुछ बीते चार वर्ष में हुआ है।

पांच सफलताओं में से चौथी है जीडीपी की तुलना में कर अनुपालन और कर में सुधार। यह अब जीडीपी के 9 फीसदी से बढ़कर 13 फीसदी हो गया है। उच्चस्तर पर देखें तो कर अधिकारियों पर कर आतंक फैलाने का आरोप लगता रहा है। परंतु निचले और मझोले स्तर पर कर प्रशासन प्रभावी रहा है। इस स्तर पर मानव हस्तक्षेप सीमित हुआ है। अगर आप बहुत बड़े कारोबारी नहीं हैं या एजेंसियां आपके पीछे नहीं पड़ीं अथवा आप राजनीतिक पीड़ित नहीं हैं तो कर अधिकारियों के साथ आपका अनुभव बुरा नहीं होगा। पांचवीं और अंतिम उपलब्धि है वस्तु एवं सेवा कर। इसके चलते तमाम दिक्कतें पैदा हुईं, भाजपा के मूल मतदाता यानी कारोबारी वर्ग में इसे लेकर नाराजगी रही लेकिन इसे लागू किया गया।

यकीनन कई क्षेत्र ऐसे भी रहे हैं जिनमें नाकामी का सामना करना पड़ा। कृषि से लेकर निर्यात तक और विनिर्माण से रोजगार तथा सुधार रहित सरकारी उपक्रमों तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सफलता नहीं मिली। आंकड़ों में हेराफेरी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सबब बनी। नोटबंदी जैसी घटना को अंजाम दिया गया जिसकी विचित्रता की तुलना चीन में माओ द्वारा गौरैयों के खात्मे के प्रयास से की जा सकती है। ऐसी चीजों को लेकर तो हम शिकायत करते ही रहे हैं और करते रहेंगे। फिलहाल हम इस दुर्लभ उदाहरण को देखें जहां यह साबित हुआ है कि अच्छी अर्थनीति हमेशा राजनीतिक दृष्टि से बुरी नहीं होती। न ही इसका उलटा हमेशा सच होता है।

गोयल के पहले अंतरिम बजट में पूर्ण बजट की सारी खूबियां

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

यह अंतरिम बजट नहीं है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को जो अंतरिम बजट पेश किया है, वह किसी भी रूप में उनके पूर्ववर्तियों- 2004 में जसवंत सिंह, 2009 में प्रणव मुखर्जी और 2014 में पी चिदंबरम द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट से कोई समानता नहीं रखता है। अब तक किसी भी अंतरिम बजट में ऐसी योजना की घोषणा नहीं की गई, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपये के सालाना खर्च का प्रावधान किया गया हो। गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है, जिसमें 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आय सहायता दी जाएगी।

वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के मुताबिक देश में 14.6 करोड़ कृषि जोत हैं, जिसमें से 86 फीसदी का रकबा दो हेक्टेयर से कम है। इसका मतलब है कि करीब 12.5 करोड़ कृषि जोत दो हेक्टेयर से कम की हैं। इस आंकड़े से बजट का आंकड़ा भी ज्यादा दूर नहीं है। गोयल के मुताबिक योजना से 12 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा होगा। इन परिवारों में से करीब एक-तिहाई उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं, इसलिए ऐसी योजना के चुनावी फायदे को कम नहीं आंकना चाहिए।

पहले किसी अंतरिम बजट में पेंशन योजना की घोषणा नहीं की गई। इसमें असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ कामगारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपये की टोकन राशि का आवंटन किया गया है। इसका लाभ केवल 15,000 रुपये से कम आय वाले कामगारों को मिलेगा। इस तरह असंगठित क्षेत्र के 25 फीसदी कामगार योजना के दायरे में आ जाएंगे।

पिछले किसी भी अंतरिम बजट में इतनी बड़ी आयकर छूट की घोषणा नहीं की गई, जितनी गोयल ने की है। गोयल ने 5 लाख रुपये या उससे कम कर योग्य आय वाले लोगों को पूरी तरह कर छूट मुहैया कराई है। उनका अनुमान है कि इसका फायदा उन लोगों को भी होगा, जिनकी सकल सालाना आय 6.5 लाख रुपये तक है। इसका फायदा अगले साल तीन करोड़ छोटे करदाताओं को हो सकता है। कुछ अन्य फायदे मुहैया कराए गए हैं। उदाहरण के लिए वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है। बैंक से मिलने वाले ब्याज पर कटौती की सीमा को सालाना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है।

दूसरे शब्दों में 2019-20 के अंतरिम बजट में कम से कम 13 करोड़ लोगों और 12 करोड़ किसान परिवारों को वित्तीय राहत मुहैया कराई गई है। आय सहायता की मासिक राशि 500 रुपये महीना ही है, लेकिन इसके ज्यादातर लाभार्थी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होंगे। ऐसे में यह योजना तेलंगाना और ओडिशा की नकद हस्तांतरण योजनाओं का प्रभावी राजनीतिक जवाब साबित होगी। अगर इस योजना को देश भर में ठीक से लागू किया गया तो इसका पूरे देश के सभी राज्यों और समाज के सभी वर्गों की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा।

इन सभी योजनाओं का कुल सालाना वित्तीय भार 99,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। ये एकबारगी दिए जाने वाले लाभ नहीं हैं, इसलिए इनका आने वाले वर्षों में भी वित्तीय भार पड़ेगा। यह राशि भारत के अगले साल के अनुमानित जीडीपी की करीब आधा फीसदी है। अंतरिम बजट को तो भूल जाएं, किसी को आसानी से यह भी याद नहीं आएगा कि हाल के वर्षों में किसी पूर्ण बजट में भी इतने अधिक लोगों के लिए इतने बड़े लाभों की घोषणा की गई हो। अगर ये पहल नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या में वोट नहीं दिला सके तो मोदी सरकार से मोहभंग और बड़ा और व्यापक होगा।

फिर भी आश्चर्यजनक बात यह है कि इन योजनाओं के बावजूद राजकोषीय हालात काबू से बाहर नहीं होंगे। वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित कर 3.4 फीसदी किया गया है, जिसका बजट अनुमान जीडीपी का 3.3 फीसदी था। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी का 3.4 फीसदी राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि इसमें पिछले साल के 3.1 फीसदी के आंकड़े के मुकाबले थोड़ी ही बढ़ोतरी होगी। सरकार ने हाल में जीडीपी के पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को संशोधित किया है। ऐसे में अंतिम आंकड़े लक्ष्यों से अलग नहीं रहने की संभावना है।

लेकिन अब भी अंतरिम बजट के राजस्व अनुमानों को लेकर कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों की तुलना में इसी वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों में जीएसटी राजस्व की कमी एक लाख करोड़ रुपये बताई गई है। इसकी भरपाई बजट अनुमानों की तुलना में निगम कर में करीब 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, सीमा शुल्क संग्रह में 17,500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और राज्यों को अनुदान एवं ऋणों में 29,000 करोड़ रुपये की कमी की बदौलत हुई है।

अंतरिम बजट के मुताबिक विनिवेश प्राप्तियां 80,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य पर पहुंचने का अनुमान है, जो अभी तक केवल 35,500 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। ऐसे में यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल काम है। अगर इन राजस्व अनुमानों में से कोई भी मार्च 2019 के अंत तक हासिल नहीं हुआ तो चालू वित्त वर्ष का राजकोषीय घाटे का अंतिम आंकड़ा चिंताजनक होगा।

बजट के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2019-20 में विभिन्न मदों पर खर्च को नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया है। सरकार का पूंजीगत खर्च इस साल 20 फीसदी बढ़ा है। यह अगले साल केवल 6 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए बजट आवंटन में मामूली गिरावट आएगी। हालांकि रक्षा बजट 2019-20 में 7 फीसदी बढ़ने का अनुमान है, जिसमें इस साल 3 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए गोयल का पहला बजट बहुत व्यापक नजर आ रहा है।

कानाफूसी

मनमुटाव की वजह?

क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल और पार्टी के नेता सुखबीर बादल, इन तीनों में से किसी ने वर्ष 2019-20 के बजट को लेकर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है। यह पहला मौका है जब पार्टी ने बजट को लेकर खामोशी बरती है, इससे पहले वह बजट की तारीफ ही करती आई थीं। पिछले दिनों पार्टी के महासचिव मनजिंदर सिंह ने एक वक्तव्य जारी करके कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी गुरुद्वारों के मामलों में दखलंदाजी बंद नहीं करती है तो शिरोमणि अकाली दल उसके साथ गठबंधन समाप्त करने पर भी विचार कर सकता है। यह थोड़ी अतिरंजित बात हो सकती है लेकिन इसकी शुरुआत उस समय हुई जब भाजपा ने पार्टी के सिख सदस्यों को ऐसे संगठनों में शामिल करना शुरू किया जो नांदेड़, पटना और दिल्ली समेत देश भर में गुरुद्वारों का संचालन करते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि केंद्र सरकार गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इन बातों ने अकाली दल के नेताओं को यह मौका दिया है कि वे मुखालफत करें। उनका कहना है कि सिख अपने धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े होंगे क्योंकि वह उन्हें किसी भी अन्य वस्तु से अधिक प्रिय है।

आपका पक्ष

किसानों-मजदूरों को बड़ी सौगात

ससंद में वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया। महात्मा गांधी कहते थे कि जब तक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचता तब तक आपके द्वारा किया गया कार्य या उस कार्य का उद्देश्य अधूरा है। महात्मा गांधी का यह कथन बजट पेश करने के दौरान महसूस किया गया। वर्तमान सरकार ने ऐसे ही कुछ निर्णय लिए हैं जिससे समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति जो 100 रुपये प्रतिदिन नहीं कमा पाते उनके लिए लाभकारी है। महात्मा गांधी का दूसरा कथन यह भी था कि भारत गांव में बसता है और भारत की आत्मा गांव में है। यह बजट भारत की आत्मा के लिए पूर्णत: समर्पित है। साथ ही यह बजट छोटे किसान और असंगठित मजदूरों के लिए भी समर्पित रहा जिनकी गांवों में आबादी अधिक है। आज भी गांवों में किसानों की संख्या अधिक है जिनके पास 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जो किसी भी कृषि योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह जानकारी का अभाव, शिक्षा की कमी है। वे बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं और न ही कोई औपचारिक ऋण की व्यवस्था होती है। शिक्षा की कमी और अज्ञानता का प्रकोप गांव में इतना ज्यादा है कि वे साहूकारों के कर्ज तले दबे रहते हैं। साहूकार जो ऋण देते हैं उसपर ब्याज की दर अधिक होती है। इससे बच्चों का भी पालन-पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता है। बजट में किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, हर 3 महीने में तीन किस्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन असंगठित मजदूरों के लिए प्रावधान किया गया है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो। सरकार ने बजट में ऐसे प्रावधान कर किसानों तथा मजदूरों की बड़ी सहायता की है। यह कदम उन मजदूरों एवं किसानों के लिए अंधेरे में चिंगारी की तरह है जो उम्मीद से कहीं ज्यादा तो नहीं पर वह चिंगारी आशा जरूर देती है। यह दोनों कदम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके सपनों के भारत के निर्माण में एक और कदम है।

देवी सिंह घोषी, जैसीनगर

केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सौगात दी है

देश में बेरोजगारी की बढ़ती दर

पिछले दिनों इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में देश में बेरोजगारी के बारे में पढ़ा। खबर के मुताबिक पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी की दर शीर्ष पर है। यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है। दूसरी ओर सरकार मैकिंजी की रोजगार दर वाली रिपोर्ट का हवाला देकर देश में बेरोजगारी में कमी की बात कह रही है। एनएसएसओ एक सरकारी संस्था है तथा इसकी विश्वसनीयता भी है। एनएसएसओ की जो भी कथित रिपोर्ट है अगर वह सही है तो वास्तव में देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 वर्षों में काफी अधिक है। सरकार को उक्त रिपोर्ट के दावे को सही ठहराने या झुठलाने के बजाय देश में रोजगार सृजन के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि इस वर्ष के आरंभ में रेलवे में रिक्तियां निकालने की बात कही गई है। सरकार अगर युवा शक्ति का इस्तेमाल करे तो भारत विश्व में आगे निकल सकता है।

किशोर कुमार, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।